भारत सरकार
परमाणु ऊर्जा विभाग
05.04.2017 को लोक सभा में
पूछा जाने वाला अतारांकित प्रश्न संख्या : 5263

परमाणु कार्यक्रम का विस्तार

5263. श्री गजानन कीर्तिकर :
डॉ. सुनील बलीराम गायकवाड़ :
कुँवर हरिवंश सिंह :
श्री अशोक शंकरराव चव्हाण :
श्री टी. राधाकृष्णन :
श्री एस. आर. विजय कुमार :
श्री सुधीर गुप्ता :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने परमाणु कार्यक्रम के विकास और विस्तार के मुद्दों से संबंधित संसाधनों के लिए आस्ट्रेलिया के मंत्री के साथ एक बैठक की है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या परिणाम रहे हैं;

(ख) क्या सरकार का विचार निकट भविष्य में यूरेनियम निष्कर्षण और उत्पादन को दोगुना/तिगुना करने का है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ग) क्या सरकार का विचार देश के पूर्वी, पश्चिमी और उत्तर-पूर्वी भागों में नए परमाणु ऊर्जा संयंत्रों (एनपीपी) के निर्माण का है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन तथा प्रधान मंत्री कार्यालय (डॉ. जितेन्द्र सिंह):

(क) जी, हाँ । माननीय राज्य मंत्री (प्रधान मंत्री कार्यालय) ने दिनांक 8 मार्च, 2017 को नई दिल्ली में ऑस्ट्रेलियाई मिनिस्टर फॉर रिसोर्सेस से मुलाकात की, जिसके दौरान दोनों पक्षों ने असैन्य नाभिकीय ऊर्जा के क्षेत्र में भारत और ऑस्ट्रेलिया दोनों के बीच परस्पर लाभकारी सहयोग बढ़ाने के संबंध में विचारों का आदान-प्रदान किया ।

(ख) परमाणु ऊर्जा विभाग का एक सार्वजनिक क्षेत्र का एक उपक्रम, यूरेनियम कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड देश में यूरेनियम वर्तमान में, झारखंड राज्य में सात यूरेनियम खानों (बगजाता, जादूगोड़ा, भाटिन, नरवापहाड़, तुरामडीह, बंडुहुरंग तथा मोहुलडीह) तथा दो संसाधन संयंत्रों (जादूगोड़ा और तुरामडीह संयंत्र) का प्रचालन कर रही है । तुम्मलपल्ली, आंध्रप्रदेश में खदान तथा संयंत्र का निर्माण कार्य आरंभ हो चुका है । व्यापक विस्तार के लिए यूसीआईएल ने एक योजना की रूपरेखा तैयार की है, जिसमें वर्तमान सुविधाओं से संधारणीय आपूर्ति बनाए रखना, देश के विभिन्न भागों में कुछ यूनिटों की क्षमता का विस्तार और नए उत्पादन केन्द्रों (खानों एवं संयंत्रों) का निर्माण शामिल

है। परमाणु खनिज अन्वेषण एवं अनुसंधान निदेशालय (पखनि) द्वारा विभिन्न भू-गर्भीय बेसिनों में पहले से ही चिह्नित किए गए संसाधनों को ध्यान में रखकर, झारखंड, आंध्रप्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना, राजस्थान और मेघालय में यूसीआईएल के मुख्य उत्पादन केन्द्रों की स्थापना की योजना है।

(ग) उत्तरी और पूर्वी क्षेत्र में नाभिकीय विद्युत संयंत्रों की स्थापना के लिए 'सैद्धांतिक रूप से' अनुमोदन प्राप्त स्थलों का विवरण निम्नानुसार है :

स्थान तथा राज्य	**क्षमता (मेगावाट)**
उत्तरी क्षेत्र	
गोरखपुर, हरियाणा	4 x 700
माही बांसवाड़ा, राजस्थान	4 x 700
पूर्वी क्षेत्र	
हरिपुर, पश्चिम बंगाल	6 x 1000

उत्तर पूर्वी क्षेत्र में, वर्तमान में, नाभिकीय विद्युत संयत्रों की स्थापना करने की कोई योजना नहीं है। आईएस 1893 के अनुसार यह क्षेत्र भूकंपीय जोन V में आता है। नाभिकीय स्थापनाओं के स्थल मूल्यांकन संबंधी परमाणु ऊर्जा नियामक परिषद के कोड के अनुसार भूकंपीय क्षेत्र V में नाभिकीय विद्युत संयंत्रों की स्थापना नहीं की जाती है।

****